

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 03/2020 जिला अलवर ।

1. सुरेश पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 24.05.2018
अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री उमाशंकर खण्डेलवाल ।

निर्णय

दिनांक-30.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 24.05.2018 के खिलाफ दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा शीर्षक अपील सुरेश बनाम तहसीलदार कठूमर में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 तथा तहसीलदार कठूमर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 07.12.2017 प्रकरण संख्या 52/2017 अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। बरवक्त बहस राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1080 वाके ग्राम कठूमर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में किसी भी रकबे पर कोई घूडा डाल कर या अन्य किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर रखा है बल्कि उक्त आराजी के पास ही अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1365 रकबा 85 ऐयर वाके ग्राम कठूमर स्थित है। अपीलांट अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर ही काबिज है और काश्त कर रहा है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट महज द्वेष भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त
संभागाध्यक्ष
जयपुर

अपीलांट ने उक्त आराजी की बंदोबस्त विभाग से पैमाइश कराये जाने का निवेदन किया किन्तु बंदोबस्त विभाग से पैमाइश नहीं कराई गई जबकि पर्चा मौका सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2017 के मुताबिक बंदोबस्त विभाग से पैमाइश कराने की सिफारिश भी की गई है। विवादित आराजी बाबत एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश कठूबर जिला अलवर के समक्ष विचाराधीन है परन्तु उसके बावजूद भी तहसीलदार कठूबर द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 तथा तहसीलदार कठूबर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 07.12.2017 प्रकरण संख्या 31/2017 अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर एवं न्यायालय तहसीलदार कठूबर जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय तहसीलदार कठूबर जिला अलवर के समक्ष पटवारी हल्का कठूबर द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने ग्राम कठूबर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 1.01 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 1080 वर्ग फुट पर जोत लगाकर कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार कठूबर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार कठूबर जिला अलवर ने दिनांक 07.12.2017 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुये तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमण रकबे से बेदखल करने व वार्षिक लगान 0.05 रुपये का 50 गुणा 3/-रुपये शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की विरुद्ध गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा शीर्षक अपील सुरेश बनाम तहसीलदार कठूबर में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2018 पारित कर अपील अस्वीकार की जाकर तहसीलदार कठूबर के निर्णय दिनांक 07.12.2017 को यथावत रखा गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूबर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम कठूबर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 1.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 1050 वर्ग फुट पर जोत लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.10.2017 को मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर दिये जाने से तहसीलदार कठूबर द्वारा दिनांक 07.12.2017 को

अतिरिक्त संभागाध्यक्ष
कठूबर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत सिविल कारावास, बेदखल एवं शास्ती के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कर पत्रावली पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलांत का अतिक्रमण यथावत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित विधिक प्रक्रिया के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं होने से अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति-सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति-सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर